

**भारत सरकार**  
**इस्पात मंत्रालय**  
**राज्य सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 320**  
**03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए**

**इस्पात की कीमतों में बढ़ोतरी**

**320. श्री महेश पोद्दार:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि लोहे और इस्पात की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है ;
- (ख) यदि हां, तो इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार कौन सी पहल कर रही है;
- (ग) क्या यह सच है कि लौह अयस्क की कीमत में बढ़ोतरी ही लोहा और इस्पात की कीमत में तीव्र बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार नहीं है;
- (घ) सरकार ने लौह अयस्क की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और
- (ङ.) क्या सरकार देश में इस्पात के उपयोग हेतु उद्यम की मांगों के अनुसार आयात में छूट प्रदान करने और इससे संबंधित नियम को सरल बनाने पर विचार करेगी?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री**

**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): सरकार ने लौह अयस्क और इस्पात की माँग और आपूर्ति में असंतुलन, जिससे हाल के महीनों में लौह और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हुई है, को दूर करने के लिए उनकी घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने हेतु उनके उत्पादन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं।

(ग): एक नियंत्रणमुक्त, खुले बाजार के परिदृश्य में घरेलू इस्पात का मूल्य माँग व पूर्ति के बाजार के कारकों और कच्चे माल के मूल्यों के रुझान द्वारा निर्धारित होता है और वैश्विक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित भी होता है। मूल्यवृद्धि में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों में अन्यो के साथ-साथ वर्तमान वित्त वर्ष में नवंबर, 2020 तक विगत वर्ष की तत्संबंधी अवधि के दौरान 152 एमटी की तुलना में लौह अयस्क का उत्पादन 112 ही था, जिसका मुख्य कारण मार्च, 2020 की नीलामी के बाद ओडिशा में 13 चालू खनन पट्टों का गैर-प्रचालन था, जिसके कारण इसकी उपलब्धता कम होने से लौह अयस्क के मूल्य में वृद्धि शामिल है।

(घ) और (ङ): लौह अयस्क की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्यो के साथ-साथ लौह अयस्क का उत्पादन/उपलब्धता बढ़ाने के लिए खनन और खनिज नीति सुधार, सरकारी खनन कंपनियों द्वारा उत्पादन एवं अधिकतम क्षमता उपयोग में तेजी लाना, सेल को 25% फ्रेश फाइन और 70 एमटी डंप तथा अवशिष्ट बेचने की अनुमति प्रदान करना, सेल द्वारा लौह अयस्क फाइन की नीलामी में तेजी लाना और ओडिशा की ज्वलत कार्यशील खदानों का राज्य एवं केन्द्र के पीएसयू आदि द्वारा जल्द प्रचालन शामिल है।